International Journal of Sociology and Humanities

ISSN Print: 2664-8679
ISSN Online: 2664-8687
Impact Factor: RJIF 8
IJSH 2024; 6(2): 120-125
www.sociologyjournal.net
Received: 25-07-2024
Accepted: 04-09-2024

रोहित पटेल
शोधछात्र (एस.आर.एफ.),
समाजशास्त्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
रोहित पटेल
शोधछात्र (एस.आर.एफ.)
समाजशास्त्र विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा का भविष्य

रोहित पटेल

DOI: https://dx.doi.org/10.33545/26648679.2024.v6.i2b.104

सारांश
शिक्षा किसी देश के विकास एवं उस देश के व्यक्तियों के पूर्ण मानव क्षमता को साकार करने, न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष समाज विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। यह मानवता के सामने आने वाले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर आलोचनात्मक विश्लेषण करनें का अवसर प्रदान करता हैं। शिक्षा वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समानता, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक प्रगति एवं सांस्कृतिक सुरक्षा के मुद्दों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच भारत की निरंतर वृद्धि एवं प्रभुत्व की कुंजी भी प्रदान करतें है। शिक्षा पद्धति को समय की जरूरतों और विश्व के बदलते परिदृश्य के अनुरूप भारत सरकार ने समय–समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किये हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से पहले भारत सरकार ने दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं 1986 (संशोधन, 1992) नीतियों का प्रारूप तैयार किया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पहले की शैक्षणिक नीतियों के खामियों को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। इस नीति में पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ और जवाबदेही ये पांच स्तम्भ नींव के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग और विकास के साथ कौशल आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में सभी शैक्षणिक स्तरों एवं चरणों, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार किए गए हैं। प्रस्तुत लेख में उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पहले के राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किस प्रकार से अलग है, इसमें क्या प्रस्तावित परिवर्तन हुए हैं? इससे उच्च शिक्षा में कैसे लाभ होगा एवं उच्च शिक्षा की भविष्य के प्रारूप का विश्लेषण किया गया है। इस लेख के द्वारा समाज के लोगों का उच्च शिक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हो रहे संसय एवं भ्रम दूर होंगे। इसके क्रियान्वयन होने से उच्च शिक्षा में आनें वाली समस्याएं और उनके निदान का ज्ञान होगा, जिससे लोगों के बीच उच्च शिक्षा को लेकर जागरूकता का विकास होगा।

कूटशब्दः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जवाबदेही, कौशल आधारित शिक्षा, उच्चशिक्षा

प्रस्तावना
शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो मनुष्य से संबंधित है। शिक्षा प्रणाली छात्रों को शिक्षार्थी, विद्वान, नवप्रवर्तक, शोधकर्ता और प्रशिक्षक बनाने में आवश्यक होती है। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का शिक्षा के संदर्भ में कहना है कि– "शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय हैं जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है।" भारत की शिक्षा प्रणाली विश्व में सबसे मजबूत और प्रभावशाली में से एक है। संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के नाते भारत अभी भी छात्रों के लिए बेहतरीन शिक्षा सुविधा प्रदान कर रहा हैं। देश में विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए अवसर प्रदान करने वाले कई विश्वविद्यालय स्थापित है। बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भी सुविधा प्रदान कराते हैं जो परिसर की संस्कृति को अधिक विविध एवं समृद्ध बनाते हैं। भारत में शिक्षा प्रत्येक स्तर पर आसानी से उपलब्ध हैं जो जनता के उपयोग के लिए एक संसाधन बनती है। भारत सरकार शिक्षा के महत्व के विषय में जनता तक पहुंचने में हर संभव प्रयास कर रही है और युवा पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वें देश एवं स्वयं के लिए एक संपत्ति बन सकें।
पिछले कुछ दशकों से निरंतर और मजबूत आर्थिक विकास के बाद भी भारत को अभी भी सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संविधान के अनुसार विद्यालय शिक्षा राज्य का विषय है, नीतियों को तय करने और उन्हें लागू करने का पूर्ण अधिकार राज्यों के पासहै। जबकि शैक्षणिक नीतियों की रूपरेखा भारत सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर तैयार की जाती है (एंडरसन एंड लाइटफूट, 2019)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधन,1992 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए गुणवत्तायुक्त मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की गई थी। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21(अ) के तहत प्रत्येक नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित किया गया (लक्ष्मीकांत, 2023:7. 12)। हालांकि इस अधिनियम ने सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित की है लेकिन

भारतीय शिक्षा प्रणाली की वर्तमान चुनौतियां वैश्विक स्तर पर विकास में बाधक बनी हुई है। हाल ही के वर्षों में भारत विश्व के बेहतर गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों की सूची में पिछड़ने की उम्मीद की जा रही थी जिससे सरकार और पूरी शिक्षा व्यवस्था इस मामले में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने और इसमें व्यापक सुधार करने की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए 34 वर्षों के बाद भारत की शिक्षा नीति में बदलाव करने का निर्णय लिया। पहली शिक्षा नीति, 1968 एवं दूसरी शिक्षा नीति, 1986 (संशोधन 1992) के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 में डॉ.के.के.कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कस्तूरीरंजन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की रूपरेखा तैयार किया और भारत में 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 देश में शिक्षा की आधारभूत समझ सहित शिक्षा के सभी स्तरों में व्यापक बदलाव लाने और लागू करने की सिफारिश किया गया है (केपीएमजी, 2020:3–29)। इसका उद्देश्य शिक्षा, विद्यालयों, विश्वविद्यालय के प्रशिक्षकों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के तरीके और शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाने का भी प्रयास किया गया है तथा इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में उन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रहा है जिसमें उच्च प्रशिक्षित अनुभाविक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। उच्च शिक्षा प्रणाली उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही थी जिसके लिए इसे प्रारंभ किया गया। सामन्यतः शिक्षा अपने आप में इतना लाभदायक व्यवसाय बन गया कि कोटा प्रणाली और राजनीतिकरण के साथ पेशेवर संस्थाओं की संख्या में वृद्धि से गुणवत्ता खो गयी। भारतीय उच्च शिक्षा पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली विकास के बावजूद मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टि से चुनौतियों का सामना कर रही है। विश्व में विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति जैसे– डेटा उपयोग, मशीनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय हुआ। कई अकुशल रोजगार मशीनों द्वारा कियें जाने लगे जिससे कुशल कार्यबल की आवश्यकता हुई विशेषतरू गणित, कंप्यूटर, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी में बहु–विषयक क्षमताओं के साथ मिलकर डांटा विज्ञान की मांग तेजी से बढ़ रही है। नुवान नोवा हरारे (2018:93–101) ने लिखा है कि ष्आने वाला समय डॉटा का होगा, जिसके पास जितना अधिक डॉटा होगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा।" वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण एवं घटते प्राकृतिक संसाधनों के साथ विश्व की ऊर्जा, जल, भोजन, स्वच्छता की आवश्यकताओं एवं सतत विकास के लक्ष्यों को कैसे पूरा की किया जाएगा इन्हें जानना, समझना होगा। महामारी एवं महामारियों के प्रकोप के लिए संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास के लिए शोध की आवश्यकता है। तेजी से बदलते रोजगार दृष्टिकोण और वैश्विक स्तर पर बच्चे न केवल सीखे बल्कि कैसे सीखें महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, खोज उन्मुख, पूछताछ–चर्चा आधारित, लचीला और आनंददायक बनाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों के सभी पहलुओं और क्षमताओं को विकसित करने के लिए गणित एवं विज्ञान के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, खेल व फिटनेस, भाषाएँ, मानविकी, साहित्य, संस्कृति एवं मूल्य को भी शामिल करना हैं। शिक्षा को सिखने वालों के लिए अधिक उपयोगी, सर्वांगीण और संतुष्टिदायक बनाना, शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों के नैतिक तर्कसंगत, दयालू बनाकर उनके चरित्र का निर्माण करना तथा साथ ही साथ उन्हें लाभकारी एवं पूर्ण रोजगार के लिए तैयार करना चाहिए (रेड्डी एंड अदर्स, 2023:1–11)। इस तरह देखा जाए तो बदलते परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की जरूरत को पूरा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवाचार व शोध को बढ़ावा देने तथा शिक्षा प्रणाली में वैश्विक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति अत्यंत आवश्यक है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किये गए बदलाव

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य नैतिक मूल्यों के साथ तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम, सहानुभूति, करुणा, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक स्वभाव और रचनात्मक विचार रखने वाले अच्छे इंसान का विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुसार समतापूर्ण, समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण के लिए संलग्न और योगदान देने वाले नागरिकों का निर्माण करना है। एक अच्छा शिक्षण संस्थान वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत और देखभाल की जाती है। शिक्षण संस्थान सुरक्षित और प्रेरक सीखने का माहौल मौजूद होता है और जहां सीखने के लिए अनुकूल भौतिक बुनियादी ढांचे व उपयुक्त संसाधन सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। इस नीति के लिए केंद्र और राज्य सरकार के निवेश का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए देश के जीडीपी के 6 प्रतिशत के बराबर निवेश करेगी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020:99)। नई शिक्षा नीति को ऐसी नीति बनाने का प्रयास किया गया है जो हमारी समझ में शैक्षणिक परिदृश्य को बदल देगी ताकि युवाओं को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकें। इसमें प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारे देश के व्यापक विभिन्न शैक्षणिक आयामों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक की शैक्षणिक व्यवस्था तय की गई है। 2030 तक प्रीस्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम 102 मॉडल के स्थान पर 5334 शैक्षणिक व्यवस्था को आधार बनाया गया (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020:8–13)। इस स्थिति में 3 वर्ष की प्रीस्कूलिंग शिक्षा तथा 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा जिसमें 3 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति को चार चरणों में बांटा गया है। बुनियादी स्तर में तीन से आठ वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें 3 वर्ष की प्रीस्कूलिंग शिक्षा, आंगनबाड़ी और कक्षा 1 व 2 की स्कूली शिक्षा दी जाएगी। जिसके तहत छात्रों के भाषा कौशल और उनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया हैं। प्रारंभिक स्तर का समय 3 वर्ष रखा गया है एवं इसमें 8 से 11 वर्ष के बच्चे शामिल है। जिसमें कक्षा 3 से 5 तक को शामिल किया गया है। इस चरण में छात्रों के संख्यात्मक कौशल को सुदृढ़ करने के साथ ही छात्रों को क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा तथा प्रयोग के माध्यम से विज्ञान, कला, गणित इत्यादि की शिक्षा दी जाएगी। मध्य स्तर की अवधि को 3 वर्ष निर्धारित की गई है। इस चरण में 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया है जिसमें विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और 6वीं कक्षा से कोडिंग भी शुरू की जाएगी। सभी बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ–साथ व्यावसायिक उद्यमिता का भी मौका दिया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा के दौरान ही बच्चों को रोजगार के योग्य बनाना है। माध्यमिक स्तर की अवधि 4 वर्ष है जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्र शामिल होंगे। इस चरण के अंतर्गत 9वीं से 12वीं कक्षा के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है और वैकल्पिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है तथा छात्र अपनी पसंद के अनुसार अपने विषय चुन सकते हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छात्रों के परीक्षाओं का बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं के प्रारूप में भी बदलाव करते हुए सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे सुधार किए गए हैं(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020:14–22)।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के विकास के साथ शिक्षण के पाठ्यक्रमों को उन्हीं के अनुरूप चरणबद्ध रूप से निर्धारित किया गया है। इस नीति के तहत शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के साथ–साथ माता–पिता को संवेदनशील बनाकर प्रत्येक छात्र की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकार करना है। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बहु–विषयक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल में अंतरूविषयक और व्यापक शिक्षा, रटने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय काल्पनिक समझ को प्रमुखता, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन और मूल्यांकनात्मक विचार प्रक्रिया, संचार, सहयोग, टीमवर्क और लचीलेपन जैसे जीवन कौशल को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है (सिल्वारानी, 2023:1–3)। इन सबके अलावा शिक्षक और सीखने में व्यावसायिक विज्ञान का बड़े पैमाने पर संचालन, भाषा की बाधाओं को दूर करना, दिव्यांग छात्रों के लिए शैक्षणिक योजना, प्रबंधन और पहुंच बढ़ाना, उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए शोध की अनिवार्यता, सतत अनुसंधान और विशेषज्ञो द्वारा नियमित मूल्यांकन के आधार पर निरंतर प्रगति, भारत की समृद्ध, विविध, प्राचीन, आधुनिक संस्कृतियों और ज्ञान प्रणालियों तथा परंपराओं पर गौरवान्वित होना एवं बढ़ावा देना इत्यादि इस नीति में बदलाव किए गए हैं, जो पहले के शिक्षा नीति से अलग हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा संबंधी बदलाव

भारत जैसे विकासशील देश के लिए उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यह मानव विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में उच्च शिक्षा में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। भारत से अनेक वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रौद्योगिकीविद, डॉक्टर, शिक्षक और प्रबंधक बने, जिनकी दुनिया भर में अत्यधिक मांग है। उच्च शिक्षा विशेषकर तकनीकी शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराए गए जनशक्ति और उपकरणों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण अब यह हमारी औद्योगिक और तकनीकी क्षमता में दस देशों में से एक है। भारत पहले ही ज्ञान प्रसार के युग में प्रवेश कर चुका है। इसने परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने प्रदर्शन से अपनी आशातीत क्षमता शाबित की है। बीते हुए कुछ दशकों में अंतरिक्ष यान, उपग्रह, इंटरनेट और वैज्ञानिक जांच की अन्य शाखाओं का आगमन हुआ। उच्च शिक्षा लोगों को मानवता के सामने आने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है। उच्च शिक्षा राष्ट्रीय विकास के लिये विशिष्ट ज्ञान और कुशल व्यक्ति प्रदान करती है।

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली छात्रों के मामले में चीन और अमेरिका के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है तथा छात्र नामांकन में दूसरे स्थान पर है (सिंह, 2011)। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी से व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। आज भारत में 60 प्रतिशत से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र द्वारा प्रसारित होते हैं। पिछले कुछ दशकों से इन शिक्षण संस्थानों की स्थापना में तेजी आयी हैं जिससे भारत विश्व में सबसे बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा संस्थानों का घर बन गया है। भारत में उच्च शिक्षा का ढांचा बहुत ही जटिल है। इसमें विभिन्न प्रकार के संस्थान जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, मेडिकल, पॉलिटेक्निक इत्यादि शामिल है। विश्वविद्यालय भी अनेक प्रकार के होते हैं जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय जो भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा गठित किए जाते हैं, विश्वविद्यालय आयोग (यूजीसी), राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय (सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त) और निजी विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था और विवरण के लिए जिम्मेदार है। विजय और अशोक (2022) के लेख से पता चलता हैं की भारत में 54 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 442 राज्य विश्वविद्यालय, 126 डीम्ड विश्वविद्यालय तथा 397 निजी विश्वविद्यालय हैं। भारत में एक संघीय व्यवस्था है और भारतीय संविधान शिक्षा को केंद्र और राज्य दोनों की समवर्ती जिम्मेदारी के रूप में रखता है। जहां केंद्र उच्च और तकनीकी शिक्षा में समन्वय और मानक तय करता है, वहीं स्कूली शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत कई नियामक निकाय और अनुसंधान परिषद जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, काउंसिल आफ आर्किटेक्चर, इंडियन कौंसिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल आफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन कौंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल,रिसर्च इत्यादि है जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दीर्घकालिक योजना विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की वर्तमान प्रणाली को समाप्त करना है और कई छोटे कॉलेज जो शैक्षणिक रूप से अव्यवहार्य एवं आर्थिक रूप से महंगे हैं उन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में विलय कर दिया जाएगा। मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़कर सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के स्थान पर एकल विनियमन भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करना है जो अंततः यूजीसी या एआईसीटीई जैसे मौजूदा नियामक निकायों की जगह लेगी। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के चार निकाय बनायें गये हैं जिनमें राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद जो शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए नियामक के रूप में कार्य करेंगी, सामान्य शिक्षा परिषद जों उच्च शिक्षा कार्यक्रमों यानि मानिकीकरण, कार्य के लिए अपेक्षित सिखने के परिणामों की रुपरेखा तैयार करेगी, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद जो मेटा मान्यता प्राप्त निकाय हैं यह मुख्य रूप से सार्वजनिक आत्म–प्रकटीकरण, सुशासन और परिणाम जैसे बुनियादी मानदंडो के आधार कार्य करेंगे, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद जो संस्था,कालेजों और विश्वविद्यालयों के लिए वितपोषण का काम करेंगे। उच्च शिक्षण संस्थान तीन स्तरीय संस्थागत प्रारूप में पुनर्गठित किया गया है– स्तर 1 अनुसंधान विश्वविद्यालय, स्तर 2 शिक्षण विश्वविद्यालय और स्तर 3 स्वायत्त कॉलेज। इस शिक्षण प्रणाली के परिणामस्वरूप उत्कृष्टता प्रदान करने, छात्रों तक पहुंच बढ़ाने और शैक्षणिक लागत को कम करने के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली को इन तीन अलग–अलग अकादमी श्रेणियां में विभाजित किया गया है (झा,2022)। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा एक नई प्रणाली अकादमी बैंक आफ क्रेडिट को लागू किया है जो विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान से अर्जित अकादमी क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में सक्षम होगा तथा इस अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखकर उच्च शिक्षण संस्थान से डिग्री प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वाभाविक रूप से पहले के उच्च शिक्षा ढाँचे में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जिसका मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के साथ इसमें सुधार करना है। कला, मानविकी, कंप्यूटर विज्ञान, विज्ञान और साहित्य का अंतरूविषयक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है ताकि ऐसे पाठ्यक्रम छात्रों के लिए कुछ कंपनियों में भर्ती के बाद नौकरी करने के लिए उपयोगी हो सकें। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट (एआईएचईएस) 2022–23 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात केवल 27.1 प्रतिशत है जो विकसित तथा अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है, साथ ही 3.5 करोड़ नयी सीटों को जोड़ना है जिसके लिए 2030 तक प्रत्येक जिले में बहु–विषयक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी (सोमानी,2023)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के एकल सामान प्रवेश परीक्षा की शुरुआत की है जो राष्ट्रीय

परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जा रही है। एकल सामान प्रवेश परीक्षा की शुरुआत एक सकारात्मक कदम है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के तनाव एवं दबाव को कम करेगा तथा आगे चलकर सभी छात्र आवेदकों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। मान्यता प्राप्त विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से पाठ्यक्रम लेकर छात्र जो अकादमिक क्रेडिट अर्जित करते हैं उन्हें संग्रहित करने के लिए अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट की स्थापना की गई है। एक छात्र पाठ्यक्रम का पूरा अंक अर्जित कर इसे अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट में जमा कर सकता है। यदि कोई छात्र कॉलेज बदलने का निर्णय लेता है तो वह इन क्रेडिट को स्थानांतरित कर सकता है। यदि कोई छात्र किसी कारण से पढ़ाई छोड़ देता है तो वह एकाधिक प्रवेश और एकाधिक निकाय के तहत बाद में आकर अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकता है तथा साथ ही उसके क्रेडिट की बरकरार रहेंगे अर्थात वह छात्र वर्षों बाद भी आकर वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकता है जहां से उसने छोड़ा था (झा,2022)। इस नीति के तहत यह प्रणाली अपनायी गई है कि 3 या 4 साल के स्नातक कार्यक्रमों में छात्र विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे और उसके अनुसार डिग्री और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। जैसे 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 साल के बाद स्नातक की डिग्री, 4 साल के बाद शोध के साथ स्नातक प्रमाण पत्र और 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र एक साल में मास्टर्स के साथ पीएचडी कर सकेंगे। इस नीति के द्वारा एम.फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की उच्च शिक्षा पर सकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव दिखलाई देने की उम्मीद की जा रही है। भारत में शीर्ष 100 विदेशी विश्वविद्यालय के संस्थानों एवं संकायों को स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। भारत शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की आकांक्षा रखी है जिसके लिए अपने शैक्षणिक संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम को भी अपनाने का प्रावधान किया हैं (रेड्डी,2021:928)। इस तरह छात्रों को अपने ही देश में वैश्विक शिक्षा की गुणवत्ता प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उन अनुभवों से देश निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का गठन किया जाएगा जों शिक्षण के साथ–साथ अध्ययन एवं मूल्यांकन करने में भी महत्वपूर्ण होंगे। वयस्कों को सीखने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी आधारित एप्स, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, सैटेलाइट आधारित टीवी चौनल, ऑनलाइन किताबें और आईसीटी से सुसज्जित पुस्तकालय एवं शिक्षा केंद्र इत्यादि का विकास किया जाएगा। ई–पाठ्यक्रम हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध होने के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे (वर्मा एंड कुमार,2021;मानस,2020)। इस तरह नई शिक्षा नीति का उद्देश्य एक समग्र और बहु–विषयक शिक्षा का लक्ष्य मानव की बौद्धिक, सौंदर्य, समाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तरीके से विकसित करना है।

उच्च शिक्षा से संबंधित चुनौतियां एवं उसका भविष्य

भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है फिर भी हम एक अच्छी और मजबूत शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सरकारें आयी और उन सरकारों ने नई और प्रभावी शिक्षण नीतियां स्थापित करने तथा बढ़ावा देने की कोशिश की लेकिन वे हमारे देश के लिए पर्याप्त नहीं थी। भारत सरकार मानती है कि नए वैश्विक परिदृश्य उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए अद्वितीय चुनौतियां पैदा करती है। यूजीसी ने कहा है कि वाणिज्य, मानविकी, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ–साथ पर्यटन, कृषि, कानून, प्रबंधन, चिकित्सा या इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न व्यावसायिक विषयों के कौशल स्नातकों की मांग की गई है (मानस, 2020)। यूजीसी उच्च शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। यहां उच्च शिक्षा प्रणाली में आ रहीं चुनौतियां एवं समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कई प्रारूपों को प्रारंभ करने तथा कुछ में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2022 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 27.1 प्रतिशत तथा 2018 में 26. 3 प्रतिशत है (एआईएसएचई, 2022)। जिसमें 5 वर्षों में मात्र 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। इस नीति के तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50 प्रतिशत करना और 3.5 करोड़ नई सीटों को बढ़ाना है। उच्च शिक्षा के नामांकन में बड़ी संख्या में शहरी जनसंख्या शामिल है जबकि ग्रामीण जनसंख्या का नामांकन बहुत ही कम है। इस तरह उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करना दुरूह कार्य हो सकता है। सकल नामांकन अनुपात और नई सीटों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढाचें व सुविधाओं और नए संकाय निर्माण की आवश्यकता होगी। भारत में खराब बुनियादी ढांचा उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए वैसे ही पहले से चुनौती बनी हुई है। संकाय की कमी और योग्य एवं कुशल शिक्षकों को आकर्षित करने व बनाए रखने में राज्य शैक्षिक प्रणाली की अक्षमता कई वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए चुनौतियां पैदा कर रही हैं (अत्री एंड अदर्स, 2019)। इस तरह बुनियादी सुविधाओं और संस्थाओं को आवश्यक एवं क्षमतापूर्ण बनाने के लिये अधिक समय और धन की आवश्यकता होगी जिससे कोष पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा जो अतिरिक्त करारोपण में वृद्धि करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष अत्यधिक मात्रा में निधि से खर्च होने के बावजूद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था की हालत खस्ता ही बनी हुई है।

अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगे शोधकर्ताओं की संख्या को अन्य देशों की तुलना में देखे तो हम पाते हैं की प्रति 10 लाख जनसंख्या पर भारत में 119 शोधकर्ता है जबकि जापान में 5287 और अमेरिका में 4484 शोधकर्ता हैं। भारत में शोधकर्ताओं की संख्या जापान, रूस, अमेरिका, चीन और जर्मनी की तुलना में काफी कम है (बनर्जी एंड रेड्डी, 2022)। हमारे यहां उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान के लिए अपर्याप्त संसाधन और सुविधाएं हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही शोधकर्ताओं को सुझाव देने के लिए गुणवत्तापूर्ण संकाय व पर्यवेक्षकों की संख्या भी सीमित है। भारत के अनेक शोध क्षेत्रों में शोधकार्य अभी अपर्याप्त है जिसका पता कोविद–19 महामारी के समय अनेक समस्याओं से जूझने से प्राप्त हुआ और यह देश को क्या पूरे विश्व को घुटनों पर ला दिया। चिकित्सा के साथ–साथ प्रौद्योगिकी, रक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी शोध की आवश्यकता बनी हुई है। इसके लिए कुशल एवं योग्य शोधकर्ताओं की कमी प्रमुख समस्या हैं तथा सामाजिक हित में कुछ अच्छे शोध होते हैं तो उनका ब्रेन ड्रेन हो जाता है जिसका लाभ देश को नहीं मिल पाता हैं।

भारत जैसे विशाल एवं विविधता वाले देश में उच्च शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है क्योंकि सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं हो पा रही है। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा ही हम विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पायेंगे (शुक्ला, 2020)। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि निजी शिक्षण संस्थान अपने ढंग से पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित करती है और पाठ्यचर्या गतिविधियों के नाम पर मनमाना शुल्क वसूल करती है। निजी विश्वविद्यालय और संस्थान लोगों से पैसे लेकर आसान और सुविधायुक्त शिक्षा और डिग्री प्रदान करा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा एक साथ एक से अधिक कोर्स करने की पहल उच्च वर्ग या फिर जो साधन संपन्न वर्ग है उनके अनुरूप हो सकती है लेकिन देश की बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबी में जीवनयापन कर रही है, वह उच्च शिक्षा

में प्रवेश ही नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह निजीकरण द्वारा महंगी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा जिससे शिक्षा नैतिक कर्तव्य न होकर व्यवसाय के रूप में सामने आयेंगी। शिक्षा के व्यापरीकरण के द्वारा देश के सभी लोगों को समान शिक्षा नहीं मिल पाएगी और इसका प्रबंधन सरकार से हटकर निजी हाथों में आ जायेगा। ऐसी शिक्षा व्यवस्था समाज के लोगों में समानता, न्याय और समावेशन को बढ़ावा न देकर अलग–अलग खेमों में बाँट देगा जो संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ तथा कल्याणकारी राज्य के रूप में देश को खतरा होगा।

हमारी शिक्षा प्रणाली अपने कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों में गुणवत्ता के समस्याओं से परेशान है। संकाय एवं कक्षों की कमी, खराब शिक्षण, शिक्षकों द्वारा समय पर कक्षाएं न लेना, छात्रों की अनुपस्थिति, भीड़भाड़युक्त कक्षाएं, पारंपरिक शिक्षण विधियां, पुराने एवं अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, अनुसंधान एवं शिक्षण में अंतर इत्यादि शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने एक रिपोर्ट दी जिसमें इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की थी कि देश में 68 प्रतिशत विश्वविद्यालय और 90 प्रतिशत कॉलेज मध्यम या खराब गुणवत्ता वाले हैं और देश के कॉलेज में आधे से अधिक शिक्षकों के पास उचित डिग्री, योग्यता एवं मानक नहीं हैं (सिंह, 2011)। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत में अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है हालांकि सरकार लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। फिर भी देश में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और कॉलेज यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है और हमारे विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालय में अपनी जगह बनाने की स्थिति में नहीं है। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय और कॉलेज में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है। छात्रों के साथ–साथ प्रोफेसरों का कर्मचारी एवं छात्रों द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वार्षिक परीक्षा एवं रटने की प्रक्रिया को हटाकर सेमेस्टर एवं समझ पर आधारित परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की है और इसमें छात्रों के प्रदर्शन के नियमित मूल्यांकन को भी शामिल किया गया है। इसके वजह से छात्रों के ऊपर से शारीरिक बोझ को कम किया गया लेकिन उनमें मानसिक दबाव बढ़ेगा जिसके कारण वें तनाव एवं अवसाद की स्थिति में आ सकते हैं। शिक्षण प्रारूप में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने और दूर–दराज में रहने वाले व्यक्तियों सहित सभी के लिये शिक्षा को सुलभ बनाने की परिकल्पना की गई है, हालांकि इसके लिए डिजिटल सुविधा और इंटरनेट जुड़ाव देश के लिए चुनौती बनी हुई हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हुई है वहां के लोगों को इसके उपयोग के प्रति अज्ञानता एवं अनभिज्ञता भी मुख्य समस्या हैं। शिक्षा प्रारूप में देश में विदेशी संकायों की स्थापना एवं उनके अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्धारण का प्रावधान किया गया है। विदेशी शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा की बात करें तो पता चलता है कि 1960 के बाद पश्चिमी देशों को लगा कि उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त एवं विकास कर लिया है, वे प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिये हैं, किसी भी महामारी या प्रकोप से बच सकते हैं लेकिन हाल ही में आये कोविद–19 महामारी ने पूरे विश्व को घुटनों पर ला दिया संपूर्ण ज्ञान धरा का धरा ही रह गया। इस तरह विदेशी संकाय एवं विदेशी पाठ्यक्रम देश के लिए कितना लाभकारी होगा इस पर संशय बना हुआ है।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सिविल सेवक, प्रोफेसर, शिक्षक के रूप में या किसी विभागीय पद पर कार्य करते हैं। इस कार्य के दौरान अनेक लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पायें जाते हैं। आईएएस, आईपीएस के घरों से जांच के दौरान काला धन पकड़ा जाता हैं। प्रोफेसर अपने संबंधियों या जान–पहचान के व्यक्तियों का साक्षात्कार के समय धन या किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन लेकर नियुक्ति कर देते हैं। इस तरह का व्यवहार अधिकांश सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता हैं जिसकी वजह से पूरा समाज नैतिकता की समस्या से जूझता है और समाज में अराजकता फैल जाती है एवं व्यवस्था से विश्वास उठ जाता हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक व्यापक दस्तावेज है जो भारत में उच्च शिक्षा में बड़े सुधारो का वादा करता है। यह नीति अनुसंधान, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और अन्य उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग के बहु–विषयक महत्व को मान्यता देती है। नीति का उद्देश्य भारत को अनुसंधान और विकास का केंद्र बनाना, दुनिया भर से प्रतिभाओं को आकर्षित करना और छात्रों को बदलते नौकरी बाजार के लिए तैयार करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति,2020 का लक्ष्य शिक्षा के प्रति अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है। यह विकास विभिन्न चरणों में बच्चों की क्षमता को पूरा करने में मदद करेगा। इसमें संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास शामिल है। ऑनलाइन शिक्षण और डिजिटल पाठ्यक्रम जैसी शिक्षण प्रणालीयों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंत में इसमें भारत में संस्कृत जैसी पारंपरिक भाषाओं को सीखने और संरक्षित करने पर भी जोर दिया गया है जो तेजी से लुप्त हो रही है। समाज को दिशा देने और विकास के लिए विश्वविद्यालय एवं कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर इसे अपनी वैधता स्थापित करनी हैं तो सार्वजनिक रूप से समर्थन हासिल करना तथा गंदी राजनीति से दूर रहना होगा। शिक्षा नीति के पांच स्तंभों पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ और जवाबदेही की अवधारणाओं को तभी क्रियान्वित किया जा सकता है जब शिक्षा व्यवस्था प्रभावी व कुशल दोनों हों। उच्च शिक्षा की विकास एवं अच्छे भविष्य को बनाए रखने के लिए भारत में संस्थाओं की संख्या और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। भविष्य की आवश्यकताओं तक पहुंचने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए शिक्षा नीतियों, वित्तीय संसाधनों, पहुंच और समानता, प्रासंगिकता, गुणवत्ता मानकों, नैतिक चरित्र और अंत में जवाबदेही पर फिर से विचार करने की तत्काल आवश्यकता हैं।

संदर्भ सूची

1. एंडरसन.जे.एंड लाइटफूट, अ.(2019).द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया : एन ओवरव्यू. ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, पेज नं0 1–53. (PDF) The school education system in India: An overview (researchgate.net) ख्अभिग्रहण 24 अक्टूबर 2023,
2. लक्ष्मीकांत, एम. (2023).भारत की राजव्यवस्था. मैग्राहिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड. ख्छठवां संशोधित संस्करण,
3. केपीएमजी(2020).इम्पैक्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड अपार्चूनिटीज एंड स्टेकहोल्डर. impact-of-national-education-policy-2020-and-opportunities-forstakeholders.pdf (kpmg.com) ख्अभिग्रहण 24 अक्टूबर 2023,
4. हरारे.एन.एन. (2018).21 लेशन फॉर द 21 सेंचूरी, हिन्दी अनुवाद, सोनी, मदन, (2020), 21 वीं सदी के लिये 21 सबक, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
5. रेड्डी वी; राव, भास्कर, भुजंगा. पी; एंड कीर्थी, जी. (2023). इस्यूज एंड इमर्जिंग चैलेंजेज फॉर एनईपी 2020. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 7(5): 1–11. (PDF) ISSUES AND EMERGING CHALLENGES FOR NEP 2020 (researchgate.net) ख्अभिग्रहण 24 अक्टूबर 2023,

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार. NEP_final_HINDI_0.pdf (education.gov.in) [अभिग्रहण 20 अक्टूबर 2023,
7. रानी,सिल्वा,एस. (2023).न्यू एजुकेशन पॉलिसी–एन ओवरव्यू एनईपी 2020 रिसर्च गेट. (PDF) New Education Policy - An Overview (researchgate.net) [अभिग्रहण 26 अक्टूबर 2023,
8. सिंह, जे.डी. (2011). हॉयर एजुकेशन इन इंडिया–इस्यूज चैलेंजेज एंड सजेशन, इडिटिंग बुक, हॉयर एजुकेशन, लैम्बर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग जर्मनी, पेज नं0 93–103. रिसर्च गेट. (PDF) Higher Education in India – Issues, Challenges and Suggestions (researchgate.net) [अभिग्रहण 27 अक्टूबर 2023,
9. विजय,एस.के. एंड अशोक, के. (2022).मेंटनिंग द रिसर्च एंड पब्लिकेशन स्टैण्र्डस इन एचईआईः ह्वाट कैन नॉलेज मैनेजर डू? आईपी इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, 7 (1) : 54–58, रिसर्च गेट. (PDF) Maintaining the research and publication standards in HEIs: What can knowledge managers do? (researchgate.net) [अभिग्रहण 27 अक्टूबर 2023,
10. झा.आशीष, (2022).नेशनल एजुकेशन पॉलिसी–हॉयर एजुकेशन रिफार्मस. National Education Policy – Highlights Higher Education Reforms (buddy4study.com) [अभिग्रहण 30 अक्टूबर 2023,
11. सोमानी, जी. (2023).नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर हॉयर एजुकेशन, मास्टर साफ्ट एक्कलेरेटिंग एजुकेशन. National Education Policy 2020 For For Higher Education (iitms.co.in) [अभिग्रहण 30 अक्टूबर 2023,
12. रेड्डी. पी.एन. (2021).नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020–चैलेंजेज एंड अपार्चूनिटीज ऑन द एजुकेशन सिस्टम, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, 10 (11) : 927–930- SR211115122335.pdf (ijsr.net) [अभिग्रहण 01 नवम्बर 2023,
13. वर्मा, एच.एंड कुमार, अ. (2021).न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑफ इंडिया : अ थियरेटिकल एनालिसिस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजिनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च, 9 (3) : 302–306. (PDF) New Education Policy 2020 of India: A Theoretical Analysis (researchgate.net) [अभिग्रहण 01 नवम्बर 2023
14. मानस, जी. एम. (2020). इस्यूज एंड चैलेंजेज इन हॉयर एजुकेशन इन इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन इकोनामिक्स एंड सोशल साइसेंस, 10 (6) : 112–119. (PDF) ISSUES AND CHALLENGES IN HIGHER EDUCATION IN INDIA (researchgate.net) [अभिग्रहण 01 नवम्बर 2023,
15. आल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिर्पोट (एआइएचईएस,2022). AIHES & Status of Higher Education 2023 | Education for All in India [अभिग्रहण 14 नवम्बर 2023,
16. अत्री,एम; स्नेहा, बी. एंड सचदेवा, एस0 (2019).हॉयर एजुकेशन इन इंडिया : इस्यूज एंड चैलेंजेज. रिसर्च गेट. (PDF) HIGHER EDUCATION IN INDIA: ISSUES AND CHALLENGES (researchgate.net) [अभिग्रहण 14 नवम्बर 2023,
17. बनर्जी, टी. एंड रेड्डी, जे. (2022).स्टेटस ऑफ हॉयर एजुकेशन इन इंडिया : चैलेंजेज, इस्यूज एंड अपार्चूनिटीज. द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलाजी. 10 (1) : 430–439. (PDF) Status of Higher Education in India: Challenges, Issues and Opportunities (researchgate.net) [अभिग्रहण 25 अक्टूबर 2023,
18. शुक्ला, अ. (2020).न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाइलाइट्स : की टेकवेज ऑफ एनईपी टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पॉवर हिन्दुस्तान टाइम्स न्यूज. New Education Policy 2020 Highlights: Key takeaways of NEP to make India a 'global knowledge superpower' - Hindustan Times [अभिग्रहण 28 अक्टूबर 2023,